



लूटे हथियार एक सप्ताह में वापस करें :भल्ला

इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हिंसाग्रस्त राज्य के लोगों से सात दिनों के भीतर लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से सौंपने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि सात दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्यपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण बीचे बीस महीनों से घाटी



और पहाड़ी दोनों में मणिपुर के लोगों की भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी समुदायों को शत्रुता को समाप्त करने और समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लौट सकें।



इसको लेकर मैं ईमानदारी से सभी समुदायों के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ी के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे स्वेच्छा से आगे आएँ और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों, गोला-बारूद को नजदीकी थानों/चौकियों या सुरक्षा बलों के शिविर में आज से अगले सात दिनों के भीतर सौंप दें।

रेखा गुप्ता बनीं दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। दिल्ली में आज से रेखा सरकार का आगाज हो चुका है। रेखा गुप्ता (50 वर्ष) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के वरिष्ठ नेता एवं अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे।

गौरतलब है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उनसे पहले



सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, जिससे यह पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ

उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वालों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह के नाम शामिल हैं।

दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला, आयुष्मान योजना को मंजूरी, सीएजी रिपोर्ट होगी पेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ सचिवालय गई। फिर शाम को यमुना आरती में शामिल हुईं। इसके बाद रात को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पहला बयान जारी कर कहा कि विकसित दिल्ली का जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। इसमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं होगा। दिल्ली से किया गया एक-एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में सीएजी की रिपोर्ट को पास किया गया। अब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा भी था कि भाजपा की सरकार बनते ही सदन में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

@खबर संक्षेप

मोदी के रहते मुमकिन नहीं है 370 की वापसी: सीएम अब्दुल्ला

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भले ही केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बताए जाते हैं लेकिन मौका आने पर उमर अपनी बात कहने से नहीं चुकते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार द्वारा किए गए दावे पुरे नहीं होते हैं तो उनकी सरकार केंद्र के साथ अपने संबंधों को लेकर पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि पीएम मोदी के रहते जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की वापसी

नहीं हो सकती है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला से जब यह पूछा गया कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बहाल होने की कोई संभावना है? उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति अपनी दृष्टिकोण को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया।

ढाका से दुबई के लिए उड़ी फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, नागपुर में कराई लैंडिंग

नागपुर। ढाका से दुबई जा रहे बांग्लादेशी एयरलाइंस के विमान में तकनीकी खराबी आने से महाराष्ट्र के नागपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 396 यात्री और 12 क्रू मंबर सवार थे।



गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर नागपुर हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते बुधवार आधी रात को विमान का मार्ग बदल दिया गया था और इसे नागपुर में लैंड करवाया गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश एयरलाइंस के इस विमान में 396 यात्री और 12 क्रू मंबर शामिल थे। आपातकालीन लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को कंपनी के दूसरे विमान से उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बांग्लादेश एयरलाइंस का यह विमान ढाका से दुबई जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसमें तकनीकी खराबी की सूचना मिली। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई।



टबुरान मानों TRENDING है...

शान ओ शौकत के लिए शासकीय निधि का दुरुपयोग
मध्य प्रदेश के डेडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने अपनी शान ओ शौकत के लिए सरकारी निधि का जमकर दुरुपयोग किया है। साहब जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के पहले साहब ने अपने सरकारी आवास में 3 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य करवाए हैं। जिसको लेकर साहब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अख्यार ने बताया कि साहब तो ठीक है लेकिन मैडम साहब से भी 2 कदम आगे हैं। मैडम ने इंटीरियर का सारा सामान बदलवा दिया। इतना ही नहीं काम पूरा होने के बाद मैडम को कलर और कुछ डिजाइन पसंद नहीं आई तो उन्होंने किए हुए काम को तुड़वा दिया और फिर से अलग डिजाइन में काम करवाया। मैडम का रौब देखकर काम करने वाले ठेकेदार भी चिंता में हैं। बताया जाता है कि साहब कुछ ही समय में रिटायर होने वाले हैं।

● अख्यार

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का इन्तजार खत्म आज मिलेगी लैपटॉप की राशि

89 हजार 700 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में सीधे पहुँचेगी 224 करोड़ रुपये की राशि



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 21 फरवरी को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप की राशि अंतरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे भोपाल के आरसीन्हीपी नरोहा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा।

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा वर्ष

2023-24 में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सिंगल क्लिक से उनके बैंक खातों में 224 करोड़ रुपये की राशि भी अंतरित करेंगे। ये विद्यार्थी वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिये दी जा रही है।

संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। लखनऊ से सड़क मार्ग से यात्रा कर राहुल गांधी सबसे पहले चुरवा सीमा पर मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद वे बछरावां के लिए रवाना हो गए।

इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखने का आह्वान कर कहा कि भाजपा सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान



भटका रही है। उन्होंने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधकर कहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है और भाजपा केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवेश वर्मा ने

आरोप लगाया, 25 कार्यकर्ताओं के साथ हमें नगर पंचायत कार्यालय में बंद कर दिया गया है। सांसद की जिम्मेदारी है कि वह यहां रहें, लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें, क्योंकि रायबरेली की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है।

धर्म संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किमी तक श्रद्धालुओं की भीड़

महाकुंभ में अब तक 57.08 करोड़ श्रद्धालु कर चुके स्नान

प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ का गुरुवार को 39वां दिन है। मेला खत्म होने में 6 दिन और शेष हैं। सुबह 10 बजे तक 51 लाख 80 हजार श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक 57.08 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। गुरुवार को भी महाकुंभ में भीड़ है। संगम तट पर भीड़ न हो, इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है।

गुरुवार सुबह से भी संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किमी तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोकना ज़रूरी है। वहां से शटल बस और ई-रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन का अनुमान है कि शुक्रवार से महाकुंभ



में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि, यह महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है।

26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला खत्म हो जाएगा। कुंभ

मेला की तारीख बढ़ाने की अफवाहों को डीएम प्रयागराज रविंद्र मंदार ने खारिज कर दिया है। इस बार 45 दिन का आयोजन है। इसके बाद तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है।

इधर, महाकुंभ से जुड़ी अफवाहों और फर्जी पोस्ट को लेकर प्रयागराज पुलिस ने अब तक 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज की है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, किंजरापु, अभिनेत्री निमरत कौर, केंद्रीय मंत्री जीवन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने संगम में स्नान किया। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संगम पहुंचीं।

नई दिल्ली वाराणसी और अयोध्या स्टेशनों पर बनेंगे स्थायी होल्डिंग एरिया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरआईटीईएस को सौंपा काम

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (आरआईटीईएस) को नई दिल्ली, आनंद विहार, गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या में स्थायी होल्डिंग एरिया डिजाइन करने का काम सौंपा गया है। दरअसल, रेलवे मंत्री वैष्णव ने रेल इंडिया तकनीकी



और आर्थिक सेवा के अध्यक्ष राहुल मित्तल के साथ बैठक की, जिसमें रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा टीम को स्थायी होल्डिंग एरिया डिजाइन करने का काम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी होल्डिंग एरिया डिजाइन को मॉडल तैयार होने के बाद इसे 60 हार्ड डेंसिटी वाले रेलवे स्टेशनों में इसका विस्तार किया जाएगा। इन स्टेशनों पर सभी अनधिकृत प्रवेश बिंदुओं को बंद किया जाएगा। ये होल्डिंग क्षेत्र अमृत स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम के साथ एकीकृत किए जाएंगे। बता दें पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, दिव्यांगजनों के लिए विशेष इंतजाम, स्थानीय उत्पादों के किोस्क और पर्यावरण-अनुकूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने 2023 में देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी।



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



**इन्वेस्ट
मध्यप्रदेश**
—अनंत संभावनाएँ—

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

24 25 फरवरी 2025, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कट-कमलों से शुभारंभ



ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025

स्वर्णिम मध्यप्रदेश के माथे पर विकास का चंदन



‘मध्य प्रदेश भारत के विकास गाथा में सबसे आगे खड़ा है, जिसने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मध्यप्रदेश अब प्रगति का प्रतीक बन गया है। व्यापार करने में आसानी, निवेशक – अनुकूल नीतियों और सतत विकास पर अपने जोर के साथ राज्य ने एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाया है, जहां नवाचार, उद्योग और बुनियादी ढांचा पनपता है। जैसे-जैसे मध्य प्रदेश अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, यह भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति और वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरने के लिए तैयार है।’

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

निवेश की अनंत संभावनाओं के साथ सशक्त नेतृत्व और उद्योगफ्रेंडली आसान नीतियां

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर मंथन करने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, मैनुफैक्चरिंग, नवकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, खाद्य प्र-संस्करण, स्टार्ट-अप, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं। समिट में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और संभावनाओं और अवसरों का लाभ उठाने के लिये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दिग्गज उद्योगपति अपने अनुभव, विचार और रणनीतियां साझा करेंगे।



औद्योगिक नीति एवं शासन स्तर पर प्रयास

समिट में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, फार्मा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव डी. वी. गनवीर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव आदि अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही जीएसआई के अपर महानिदेशक धीरज कुमार, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के निदेशक हितेश वैद्य और अन्य विशेषज्ञ भी मध्यप्रदेश में उद्योगों के विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

टेक्सटाइल और मैनुफैक्चरिंग

मध्यप्रदेश टेक्सटाइल और मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। राज्य की अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। समिट में टीडब्ल्यूई ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ इंगो सोलर, एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के चेयरमैन रिजु झुनझुनवाला, सेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक रीनशा सेखानी और प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्रेयस्कर चौधरी टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।



हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर

मध्यप्रदेश फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में सहजना एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष राजीव छिब्बर, इन्वोल्यूशन हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक श्री गौरव अग्रवाल, बायो-मेरिट्यू इंडिया के प्रमुख बिवाश चक्रवर्ती, सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्लोबल हेड ऑपरेशंस राहुल अवस्थी और आईपीसीए लेबोरेट्रीज के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार जैन विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

नवकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी

ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन रहा है। टाटा पॉवर के श्री दीपेश नंदा, ओ-2 पॉवर के पराग शर्मा, अवाडा एनर्जी के विनीत मितल, रिन्यू पॉवर के सुमंत सिन्हा, जिलद के अमित मितल, वारी एनर्जी के पंकज दोशी, ग्रीनको के अनिल कुमार चेलमुनशेट्टी और एसईसीआई के चेयरमैन रामेश्वर गुप्ता जैसे प्रमुख निवेशक राज्य में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

जीआईएस में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान पार्टनर कंट्री



ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान जैसे विकसित राष्ट्र पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह वैश्विक प्रतिनिधित्व मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है। नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में राजदूतों, निवेशकों, नीति-निर्माताओं और विभिन्न सेक्टर के उद्योगपतियों से संपर्क कर मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया। निवेशकों के लिए सहज प्रक्रियाएं, पारदर्शी नीति ढांचा और 24x7 सरकारी सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नवाचार, स्टार्ट-अप, और मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लाई जा रही हैं, प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। जीआईएस-2025 से मध्यप्रदेश निवेश अभियान के अगले सोपान में प्रवेश कर रहा है। राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य आयोजन किया जाएगा।



कृषि और खाद्य प्र-संस्करण

कृषि और खाद्य प्र-संस्करण उद्योग क्षेत्र में आईटीसी एम्री बिजनेस डिवीजन के गणेश के. सुंदररमन, पेक्सिको इंडिया के अनुकूल जोश, ग्रीन ग्रेन के प्रतीक शर्मा और आईएफसी वर्ल्ड बैंक के विजयसेकर कलवकोंडा निवेश और विकास की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

स्टार्ट-अप और नवाचार

स्टार्ट-अप और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनोपुरु के संस्थापक एवं सीईओ वैदंत जैन, स्टार्ट-अप मिडिल ईस्ट के संस्थापक एवं सीईओ सिबी सुधाकरण, दुबई स्थित सैव की संस्थापक श्रीमती पूवी मुनीत, एम-केपीन एवं हाइफेन के सह-संस्थापक तरुण शर्मा और सिकल्स के चांसलर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे युवा उद्यमी और निवेशक इस क्षेत्र में नए अवसरों पर मंथन करेंगे।

वित्त एवं निवेश

मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण वित्तीय क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बीएम फिनटेक के संस्थापक अनुज गोलेवा, एक्वा निमिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी के प्रबंध भागीदार राजेश सहवाल, आईटीआई ग्रोथ फंड के जनरल पार्टनर मोहित गुलाटी, युनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के प्रबंध भागीदार भास्कर मजूमदार और इन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अविनाश गुप्ता राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी

मध्यप्रदेश का पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इस क्षेत्र में ताज होटल्स, रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस के सीईओ पुनीत चटवाल, वंडरला होलीडेज लिमिटेड के अध्यक्ष शिवदास एम और एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र के विशेषज्ञ अजीत बजाज शामिल हैं। बिग बॉस के वॉयस ऑफ स्टारट्रिज विजय विक्रम सिंह भी समिट में विशेष प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे हैं।

‘मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। निवेश-अनुकूल नीतियां, मजबूत बुनियादी ढांचा और नई औद्योगिक नीति इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहे हैं। जीआईएस 2025 में विभिन्न सेक्टरों के उद्योगपतियों, विशेषज्ञों और निवेशकों की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश अब केवल एक औद्योगिक प्रदेश नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश का केंद्र बनता जा रहा है।’

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश



म.प्र. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय

नवाचार से विश्वस्तरीय बनेगा लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

आपूर्ति होगी आसान, लागत पर लगेगी लगाम

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में रूक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों मिलेंगी। पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार पोर्ट टर्न अराउंड समय को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इससे राज्य की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुधारा जा सकेगा। साथ ही पीसीएस-वन प्रणाली से ई-डिलीवरी आदेशों को पेश किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेड लेब बनाई जाएगी, जिससे उत्पाद सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता मानकों खरे उतर सकेगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डोर (आरएफआईडी) जैसे तकनीकी नवाचार सुरक्षा को बढ़ाएंगे और माल की आवाजाही भी तेज होगी। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के समावेश से लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में डेटा का आदान-प्रदान सरल और तेज बनेगा। पॉलिसी के नवाचारों में ग्रीन कार्बन योजना भी शामिल है, जो ऐसे लॉजिस्टिक्स संचालकों को शीर्ष मंजूरी देगी, जो ग्रीन-ट्रांसपोर्टेशन को अपनाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से बढ़ेगी परिवहन दक्षता

अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रही है। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो माल ढुलाई को सुगम बनाएंगे। परिवहन लागत कम होने से व्यवसायियों का लाभ बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित होगा।

निर्यात क्षमता बढ़ाने विकसित होगा विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का एक महत्वपूर्ण अंग राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाना भी है। इसके लिए पॉलिसी में निर्यात पार्क विकसित किए जाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इन पार्कों के विकास को स्टॉप ड्युटी और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपए अथवा प्रति एकड़ 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। निर्यातकों के लिए सामान्य प्र-संस्करण सुविधाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रीलायजेशन को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन की शून्य तरल प्रणालियों और केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

पॉलिसी में निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा, निर्यात-उन्मुख इकाइयों की दक्षता बढ़ाना और सुदृढ़ निर्यात-मुख्य लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पॉलिसी के उद्देश्यों में निर्यात की मात्रा बढ़ाना, ‘मेड इन मध्यप्रदेश’ उत्पादों के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी शामिल है।

घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिये सुनहरा अवसर

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से व्यापारियों और उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में लाखों नई नौकरियां उपलब्ध होंगी। विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर परिवहन और भंडारण सुविधाएं मिलेंगी।

चीन- रूस व भारतीय अवैध प्रवासियों के साथ अमेरिका का भेदभाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अवैध प्रवासियों की तीन खेप को सेना के विमान में भारत भेज दिया है। 300 से अधिक भारतीय अवैध प्रवासी भारत वापस लौट चुके हैं। खास यह है कि इन सभी को हथकड़ियों और वैडियो में जकड़ कर भेजा गया है। सेना के लड़ाकू विमान जिसमें बैठने के लिए सीट नहीं होती हैं, खाने–पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक इमरजेंसी टॉयलेट भरा होता है। उसमें अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका में चीन और रूस के तीन लाख से अधिक अवैध प्रवासी रह रहे हैं। चीन और रूस के अवैध प्रवासियों को भेजने की कोई प्रक्रिया अमेरिका द्वारा शुरू नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा पूरी तरह से अब जग जाहिर हो गया है। वह भारत और भारत के अवैध प्रवासियों के साथ अपनी ख़ुनस निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस द्वारा अवैध प्रवासियों को जिस तरह से भारत भेजा गया, उसका वीडियो बनाया गया। वैडियो और हथकड़ियों में जकड़े महिला, पुरुषों और बच्चों को भेजने का यह वीडियो 5 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में देख चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके सलाहकार एलन मस्क वीडियो में अटहास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका जानबूझकर भारत के अवैध प्रवासियों के साथ गुलाम और अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। भारत की जो विश्व गुरु वाली छवि सारी दुनिया के देशों में बनी हुई थी उस छवि को सुनयोचित रूप से नष्ट किया जा रहा है। अमेरिकी गृह मंत्रालय के अनुसार चीन के 2600000 रूस के 300000 से ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों के भी लाखों अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन भारत के अवैध प्रवासियों को अमेरिका से जिस तरह से वापस भेजा जा रहा है उससे यह बात स्पष्ट हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दुस्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले चीन और अन्य देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन एक महीना होने को आ गया चीन और अन्य देशों के साथ उन्होंने जो धमकी दी गई थी उसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की। सारी गाज भारत के ऊपर गिरती हुई दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों तंज कसा है, भारत के पास ख़ूब पैसा है। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करने वाला देश है। यह कहते हुए उन्होंने जो भारत को सहायता दी जा रही है उसे भी बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका की धमकी के आगे भारत ने बहुत सारी चीजों में आयात शुल्क घटा दिया है। अमेरिका के दौर में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस समय अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे समझौते किए हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह हैं। यह माना जा रहा था कि अवैध प्रवासियों को लेकर वह सकारात्मक रुख अपनाएंगे। भारतीय कारोबार गौतम अडानी को लेकर सकारा अमेरिका का सकारात्मक रुख होगा, लेकिन 18 फरवरी को अमेरिका न्याय विभाग ने जो पत्र भारत सरकार को भेजा है उसके बाद यह आशा भी खत्म हो गई। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क जानबूझकर भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह अपनी व्यक्तिगत ख़ुनस निकाल रहे हैं। भारत सरकार अमेरिका के इतना क्यों डर रही है, इसको लेकर अब दुनियाभर में चर्चा होने लगी है। छोटे से छोटे देशों ने अमेरिका के ऊपर जवाबी हमले किए, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौन साधना पड़ा। भारत सरकार की चुप्पी सभी को आश्चर्य चकित कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साक्षी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यह बताया है कि भारत के प्रचानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे मिले थे तब उन्होंने प्रतिस्पर्धी टैरिफ लगाने की बात उन्हें बता दी थी। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर भी उनसे चर्चा हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है, भारत सरकार कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। बहरहाल दुनिया के देशों में भारत की जो छवि बनी हुई थी वह बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। अब तो लोग यह भी कहने लगे हैं अमेरिका की सरकार भारत के साथ गुलामों सरीका व्यवहार कर रही है। पिछले 1 महीने में अमेरिका की सरकार ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वह किसी की रास नहीं आ रहा है। लोग अब 1971 के युद्ध से तुलना करने लगे हैं। उस समय भारत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था। उस समय भी अमेरिका आर्थिक दादागिरी भारत के साथ नहीं कर पाया था। 2025 में जब हम आर्थिक एवं सामरिक रूप से हजारों गुना ज्यादा समृद्ध हों, तब भारत के साथ अमेरिका इस तरह की दादागिरी कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत के साथ–साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी रूप से होता हुआ दिख रहा है।

शिक्षण से परे

तनाव समकालीन जीवन का पर्याय बन गया है। की ज़रूरत है यह स्वीकार करने का समय है तनाव स्थानिक है और यह समझने के लिए कि इसे इस तरह से कैसे संभलना है जो जीवन को जीवंत और पूर्ण रहने की अनुमति देता है। अक्सर एक सफलता और के रूप में खारिज कर दिया आसान काम, समकालीन अध्ययनों से पता चलता है कि जब तनाव और बर्नआउट की बात आती है तो शिक्षण उच्च रैंक करता है। ब्रूड के बावजूद इसमें जिम्मेदारी शामिल है, शिक्षण में एक कैरियर यादातर व्यवसायों की तुलना में आर्थिक रूप से कम आकर्षक बना हुआ है। एक शिक्षक बर्नआउट को कैसे रोक सकता है और एनडी अधिक पूर्ण तत्व एन उत्तम जीवन को रोक सकता है? एक व्यवसाय अपने आप को याद दिलाए कि आपने शिक्षक बनने के लिए क्यों चुना। शायद आप अपने शिक्षकों से प्रेरित थे या महसूस करते थे कि वक्तों के साथ काम करने से आपको खुशी मिलती है। तनाव के समय इसे याद रखने से मदद मिल सकती है आप उन तत्वों से जुड़े रहते हैं जो शिक्षण को व्यवसाय बनाते हैं न कि केवल नौकरी। शामिल करने के लिए अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं नियमित आराम–देखभाल। पर्याप्त नींद लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना (20 मिनट की सैर या योग करना), समय पर भोजन करना, और परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता का समय आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। शौक और जुनून की खेती करें जो आपको विषटित करने की अनुमति देते हैं। इसे पढ़ना, क्रॉसिग, कढ़ाई, पेंटिंग, ऑरिगामी और पेपरक्राफ्ट, बागवानी, या स्वयंसेवक काम करने है, शिक्षण से परे अपनी प्रतिभा का पता लगाते हैं नियमित पुनः एक्शन और माइंडफुलनेस प्रथाओं या कुछ ऐसा करने के लिए समय निकालें जो आपको प्रेरित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं का जायजा लेने की अनुमति देता है। यह एक दायरी लिखने के रूप में सरल हो सकता है, का उपयोग कर यूट्यूब वीडियो नई चीजों को सीखने और अभ्यास करने के लिए, या सुझावक संगीत सुनने के लिए। हमारे साधियों के साथ अनुभवों, चुनौतियों और सफलताओं को साझा करके एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करें। आपके सहयोगियों के होने की अनूठी चुनौतियों के साथ सहानुभूति रखने की सबसे अधिक संभावना है एक अध्यापक। वे विभिन्न परिणयोजनाओं पर व्यावहारिक सलाह, संरक्षक और सहयोग कर सकते हैं। समूह गतिविधियों में भाग लेना साथी शिक्षकों के साथ जुड़ने और बंधन बनाने का एक शानदार तरीका भी है, इसे व्यंजनों, पोलक, या पोस्ट स्कुल वातलाप के माध्यम से साझा करें। के छोटे जीत का जश्न मनाएं अपने शिक्षार्थियों ताकि ध्यान केंद्रित बड़े परिणामों पर (जैसे परीक्षण परिणाम) अपने महसूस नहीं करता है। क्या एक संघर्षशील छात्र ने आज एक नई अवधारणा को समझा? क्या आपने एक शांत छात्र तक पहुंचने का प्रबंधन किया? ये छोटे उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं और अपनी प्रेरणा को ऊंचा करें। यात्रा करने और नए स्थानों की खोज करने के लिए डाउनटाइम के रूप में अकार्दमिक ब्रेक का उपयोग करें जो आपको मानसिक और भावनाओं को रिचार्ज करने की अनुमति देते हैं सहयोगी। शिक्षण उचित अवकाश लेने के लिए निर्धारित ब्रेक और ओ द्रष्टव समय के साथ आता है। इन सबसे ऊपर, शिक्षण एक रचनात्मक पेशा है, इसलिए उन शान बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेें वकईति और पाठ योजना। एक मजाक या दो को हर बार कैंक करें, छात्रों को लचीलापन, ध्यान और अनुशासन के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करते हुए जीवन् के हल्के पक्ष को देखने में मदद करें। औपचारिक कार्यक्रम तनाव के प्रबंधन के साथ शिक्षकों का समर्थन एक ऐसी चीज है जिस पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने जीवन में अधिक संतुलन शामिल करने के लिए रास्ते बनाकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ संस्थानों में अक्सर औपचारिक सहाह कार्यक्रम और सहयोगी समूह होते हैं जो शिक्षकों को नियमित माइंडफुलनेस सत्र, गतिविधियों, शौक वलंबों और वेलनेस सेमिनार आयोजित करने जैसे अधिक सहायक तरीकों से एक–दूसरे से जुड़ने की अनुमति देते हैं।

संपादकीय जनजातीय हितों व श्रद्धा पर केंद्रित हो नई वननीति

डॉ. प्रवीण गुग्गानी

वनग्राम, वनों से सटे राजस्व ग्राम, जनजातीय समाज, वनों के भीतर कृषि का अधिकार, जनजातीय



समाज को वनों के सीमित उपयोग की अनुमति आदि–आदि विषय मग्न में एक बड़ा सामाजिक सरोकार का प्रश्न रहे हैं। यह प्रश्न अब गहरा रहा है। मग्न सरकार कंपनी, संस्था, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था को

बिगड़े जंगल अनुबंध पर साठ वर्ष हेतु देने के प्रस्ताव पर विचाररत है। नई नीति में निजी क्षेत्र को, विभाग के अनुसार नए पौधे लगानें होंगे। दो वर्ष में पौधे नहीं उगे तो अनुबंध समाप्त का अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेगा। इन वनों का कार्बन क्रेडिट, वन विभाग के माध्यम से विक्रय करेंगे। इस नीति के अनुसार एक हजार हेक्टेयर तक के जंगल को यदि कोई निजी कंपनी विकसित करना चाहेगी तो वनों की पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। अनुबंधित वनों से प्राप्त वनोपज का पाँचवा भाग वन समिति को और शेष चार भाग वन विकास निगम और निजी कंपनी को मिलेंगे। फल वनोपज का आधा भाग निजी कंपनी को प्राप्त होगा।

मग्न में पंचानव हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र है जिसमें से सैतीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिगड़े वन हैं। इसे ही निजी क्षेत्र में सौंपने का तैयारी है। नई नीति के अन्तर्गत निजी निवेशकों का इन वनीय क्षेत्रों की, उपज, व कार्बन क्रेडिट पर प्रथम अधिकार होगा। नई नीति का नाम सीएसआर एवं कंपनी एनवायरोनमेंट रिसार्सिबिलिटी एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वनों की पुनर्स्थापना है। इसके अंतर्गत मग्न में निजी

निवेशक न्यूनतम दस हेक्टेयर वन का चयन कर सकेंगे। नई वन नीति में कई विसंगतियाँ हैं, जिससे वनीय विविधता की हत्या हो जाएगी। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य के कारण मग्न व अन्य प्रदेशों की कृषि विविधता समाप्त हो गई है, उसी प्रकार वन विविधता समाप्त हो जाएगी। जब वनीय विविधता समाप्त होगी तो सर्वप्रथम वनीय जैव विविधता, बड़ी तोत्रता से समाप्त होगी। वनवासियों हेतु हर वृक्ष का हर उत्सव व ऋतु में अलग अलग आस्था का सम्बंध होता है। हजारों–लाखों प्रकार के जीव–जंतुओं का भोजन, उनकी औषधियां, उनकी रहवासी आवश्यकताएँ सभी कुछ समाप्त हो जाएँगे। जीव–जंतु तो छोड़िए जनजातीय समाज और नगरीय समाज को मिलने वाली हजारों वनीय औषधियां, जड़ी–बूटियाँ, रसायन, मौसमी, उत्पाद सभी कुछ समाप्त हो जाएँगे। प्रकृति की अविरल धारा के समक्ष एक बड़ा अवरोध व परिवर्तन उपस्थित होगा जिससे कई प्रकार की असंगतियाँ–विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी। अनुबंध पर जंगल लेने वाले व्यसायी केवल लाभ से सरोकार रखेंगे। निजी वन व्यवसायी और कम्पनियाँ आदि; राष्ट्रीय, पर्यावरणीय, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों के प्रति कोई सरोकार या संवेदनशीलता रखने से तो रहे। व्यावसायिक लाभ ही एकमेव लक्ष्य होगा, इससे वनोपज में असंतुलित वृद्धि तो हो सकती है किंतु पर्यावरिणी हानि, जैव व वन विविधता की हानि व वनवासी समाज के साथ शासन व शेष समाज के सम्बंध बिगाड़ सकते हैं। नई वन नीति की सम्पूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है। या तो यह नीति रद्द हो या फिर इस नीति में वनीय, विविधता, जैव विविधता, जलीय सरंचनाओं, वनीय पशु–पक्षियों की आवश्यकताओं, वनवासी बंधुओं की आजीविका

सामाजिक ताना-बाना बिखेर रहे फूहड़ता और रील्स के परिवेश

मॉर्डन परिवेश में जीवन का चरमसुख ऑफ फॉलोअर्स पाने और कमेंट आने पर निर्भर हो गया है। फ़ेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर नग्न अवस्था में तस्वीरें शेयर कर आज लाइक्री लाइक कमेंट पाकर खुद को ऐसे अनुगृहित करती दिखाई देती है; मांजो जीवन की सबसे अहम और ज़रूरी उंचाई को उन्होंने पा लिया हो। इस नग्नता को हम आधुनिकता के इस दौर में न्यू फैशन कहते हैं।

सोशल मीडिया पर फैशन की उबाल आई तो सोशल नेटवर्क पर युवा पीढ़ी ने खुद को खूबसूरत युवतियों से पीछे पाया, फिर क्या युवकों ने खुद की नग्नता का नंगा नाना शुरू किया कहां मैं पीछे कैसे? युवा अपने यौवन को दिखाते घूम रहे हैं मैं किसी से कम नहीं। पहले के ज़माने में बड़े बुजुर्ग इस तरह की हरकतों पर नकेल समक्ष थे। खेर जमाना आधुनिक है इस लिए समाज इसे स्वीकारता और आनंदित होता है। ऐसे बिगडैल यूट्यूबर के इंटरव्यूज हमें और कमेंट आने पर निर्भर हो गया है। फ़ेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर नग्न अवस्था में तस्वीरें शेयर कर

आज लड़कियाँ लाइक कमेंट पाकर खुद को अनुगृहित करती दिखाई देती है, मानो जीवन की सबसे अहम और ज़रूरी ऊंचाई को उन्होंने पा लिया हो। इस नग्नता को हम आधुनिकता के इस दौर में न्यू फैशन कहते हैं। सोशल मीडिया पर फैशन की उबाल आई तो सोशल नेटवर्क पर युवा पीढ़ी ने खुद को खूबसूरत युवतियों से पीछे पाया, फिर क्या युवकों ने खुद की नग्नता का नंगा नाच शुरू किया और कहा, मैं पीछे कैसे? युवा अपने यौवन को दिखाते घूम रहे हैं मैं किसी से कम नहीं। ऐसे बिगडैल यूट्यूबर के इंटरव्यूज होना और भी अचरज की बात है। पहले के ज़माने में बड़े बुजुर्ग इस तरह की हरकतों पर नकेल कसते थे। खेर जमाना आधुनिक है इस लिए समाज इसे स्वीकारता और आनंदित होता है। पर ये बहुत ही गम्भीरता से सोचने का विषय है–हमारे घरों के छोटे–छोटे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। माता–पिता क्यों जानबूझ कर अनदेखा कर रहें हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों को टाईम और संस्कार देना चाहते हैं? क्यों अपने हाथों अपने बच्चों को दलदल में धकेल रहें हैं। आजकल के माता–पिता बहुत ज्यादा मार्डन हैं और उन्हें नंगापन, बॉयफ्रेंड और मार्डन परिवेश बेहद आकर्षित करती है।

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मज़बूत और रचनात्मक विपक्ष आवश्यक है

विपक्ष एक आवश्यक प्रहरी है जो एक समृद्ध लोकतंत्र में सरकार की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्त करने, समाज के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने तथा सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है। सहिष्णुता, वास्तविक राजनीतिक विरोध, तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की नागरिकों की क्षमता में विश्वास, ये सभी लोकतंत्र के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं।

प्रियंका सौरभ

एक कमजोर और बिखरा हुआ विपक्ष चुपचाप खड़ा रह सकता है और बहुमत वाली पार्टी की तानाशाही और मनमर्जी को तानाशाही स्थापित करने की इजाज़त दे सकता है। यद्यपि सरकार के सुचारु संचालन के लिए एक स्वस्थ विपक्ष आवश्यक है, ताकि कभी–कभार होने वाली ज्यादतियों का प्रतिकार किया जा सके और अवरोधों को रोक़ा जा सके, किन्तु विपक्ष की अनुपस्थिति समग्र रूप से लोगों की स्वतंत्रता और जीवन को ख़तरे में डाल देगी तथा कानून के शासन को भी ख़तरा पहुँचाएगी। लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर रचनात्मक रूप से काम करना होगा। लेकिन भारत में संसदीय बहसों में बढ़ते ध्रुवीकरण, बार–बार व्यवधान तथा गहन चर्चाओं पर बयानबाजी के प्रभुत्व के कारण विधायी विचार–विमर्श की गुणवत्ता और भी ख़राब हो गई है। अन्याय नीतिगत चर्चा सरकार और विपक्ष के बीच वास्तविक बातचीत में बाधा डालती है। पक्षपातपूर्ण मुद्दों का उपयोग अक्सर एक महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने

भोपाल, शुक्रवार 21 फरवरी 2025

04

कुछ जीव माइक्रोप्लास्टिक को खाते हैं और उसे बहुत बड़े खतरे में बदल देते हैं

आदि विषय में सुरक्षा की गारंटी हो। नई वन नीति में जिसे बिगड़े वन कहा जा रहा है, उसकी परिभाषा भी तय नहीं है। ग्राम सभा की अनुमति की शर्त भी बड़ी ही आसान व एक औपचारिकता मात्र है। केवल मूल्यवान लकड़ी प्रदान नहीं करने वाले वनों को बिगड़ा हुआ वन मान लेना एक बड़ी प्रदूषित, शोषक, स्वाार्थी व एकपक्षीय नीति है। वनवासी बंधुओं की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं को एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए वनीय विविधता बनी रहना परम आवश्यक है। इस नई वन नीति से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कई वनीय उत्पादों के केवल नाम ही सुन पाएंगी। आज जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में केवल दो चार प्रकार के अन्न का उत्पादन हो रहा है व शेष फसलों का उन्मूलन होता जा रहा है वही स्थिति वनों में भी देखने को मिलेगी। प्रत्येक ऐसे वृक्ष को जिससे आर्थिक लाभ नहीं होता है या कम लाभ होता है उसे कुल्हाड़ी की बलि चढ़ाकर, वहाँ व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से मूल्यवान पेड़ लगा दिए जाएँगे। लाभ मात्र के मूलमंत्र से पारिस्थितिकी संतुलन व इको सिस्टम समाप्त होगा। वनों में ये कंपनियाँ बेतहाशा इको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगी, यह लाभप्रद तो अवश्य ही होगा किंतु इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आश्ंका है कि, वनों को लेकर ‘अंधाधुंध दोहन की’ या केवल ‘लाभ की नीति’ से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समय भी इस प्रस्ताव को लाया गया था जो बाद में फाइलों में बंद हो गया था। फ़ाइलों में बंद इस ज़िन्न को मग्न वन विभाग के नौकरशाहों ने पुनः बाहर निकाला है। यद्यपि यह मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की संवेदनशीलता ही है कि सरकार ने अभी एकतरफ़ा निर्णय नहीं लिया है, तथापि मुख्यमंत्री जी को

जनजातियों के प्रति असंवेदनशील, वन नीति से सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता मे कुछ ही दिन पहले एक डाकघर फोर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपने परंपरागत वन क्षेत्र के पुर्नर्निर्माण, संवर्धन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार देने का निर्णय हुआ था। संभवतः इसी को ध्यान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वन नीति के प्रारूप को अभी सहमति नहीं दी होगी।मग्न शासन ने नई वननीति के संदर्भ में apccfit.mp.gov.in पर जनता से सुझाव व आपत्तियाँ माँगी हैं। सभी पर्यावरणविदों को सुझाव देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि शासकीय आय बढ़ाने के इस उपक्रम को वन शोषण का धतकर्म बना दिया जाए। वन विकास के नाम पर कहीं हमारें वन व्यवसाइयों व दलालों की भेंट न चढ़ जाएँ। मग्न की जनता से प्राप्त होने वाले सुझावों और आपत्तियों को देखते हुए नीति में वांछनीय परिवर्तन या संपूर्णतः अस्वीकृत भी किया जा सकता है।

मग्न की भाजपा सरकार की ओर से यह एक शुभ संकेत है और एक अवसर भी। वस्तुतः स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट 2023 में यह निष्कर्ष था कि मध्यप्रदेश, सन्त्यान्वैहिक वनारण्य किमी वनक्षेत्र वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें यह तथ्य भी उभरकर आया था कि, 2021 की तुलना में, 2023 में, मग्न में 612 वर्ग किमी जंगल कम हो गए हैं। मग्न में चालीस प्रतिशत से कम घनत्व वाले वनों को बंजर भूमि या ओपन फॉरेस्ट कहा गया है। इस वनभूमि में वांछनीय परिवर्तन या संपूर्णतः प्रस्तावित है। मग्न सरकार का लक्ष्य इस बंजर भूमि पर वनक्षेत्र बढ़ाना है।

लेखक- जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार, राजभाषा

कुछ जीव माइक्रोप्लास्टिक को खाते हैं और उसे बहुत बड़े खतरे में बदल देते हैं

अवीव विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में चिंताजनक जानकारी सामने आई है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भीतर माइक्रोप्लास्टिक कण कैसे परिवर्तित होते हैं, जिससे समुद्र के खाद्य जाल के स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियाँ पैदा होती हैं। शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे फ़िल्टर–फीडिंग समुद्री जीव माइक्रोप्लास्टिक्स के व्यवहार और संरचना को बदल देते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण के लिए अप्रत्याशित जोखिम पैदा होते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की जांच जबकि पिछले शोध में समुद्री जानवरों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक ग्रहण करने के खतरों का दस्तावेजीकरण किया गया था, यह अध्ययन एक कदम आगे बढ़कर यह पता लगाता है कि फ़िल्टर फ़ीडरों के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद ये कण कैसे बदलते हैं। पीएचडी छात्र इंडन हेरल, प्रोफ़ेसर नोआ शेनकर और तेल अवीव विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर इनेस ज़ुवर द्वारा संचालित, अध्ययन एस्क़िडियन - समुद्री जानवरों पर केंद्रित है जो पानी से छोटे कणों को कुशलात से फ़िल्टर करते हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि फ़िल्टर फ़ीडर और माइक्रोप्लास्टिक्स के बीच की बातचीत इन कणों के प्रसार और परिवर्तन में कैसे योगदान करती है। शेनकर ने बताया, -हमारा लक्ष्य यह जांचना था कि समुद्री जीव के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद प्लास्टिक कैसे और कैसे बदलता है और यह प्रक्रिया प्लास्टिक की उपस्थिति और अन्य जीवों में इसकी उपलब्धता को कैसे प्रभावित करती है।+ फ़िल्टर फ़ीडर माइक्रोप्लास्टिक को कैसे बदलते हैं एक नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने जलद्वारा माइक्रो जल वातावरण का अनुकरण किया और दो प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक कणों को पेश किया। इन कणों में पॉलीस्टाइन (पीएस), एक सामान्य

पारंपरिक प्लास्टिक, और पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए), एक बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक शामिल है जिसे पर्यावरण के अनुकूल के रूप में विपणन किया जाता है। टीम ने 48 घंटों तक निस्पंदन, पाचन और उत्सर्जन प्रक्रियाओं की निगरानी की। परिणामों से पता चला कि दोनों प्रकार के प्लास्टिक के बीच काफी अंतर है। एस्क़िडियन ने दो घंटे के भीतर पानी से 90% पॉलीस्टाइन कणों को हटा दिया, लेकिन पाचन के 48 घंटे बाद ये कण पानी में फिर से शामिल हो गए। दूसरी ओर, पॉलीलैक्टिक एसिड कणों की सांद्रता में काफी कमी आई और वे निम्न स्तर पर बने रहे। बड़े पीएलए कण पाचन के दौरान टूटते हुए दिखाई दिए - संभवतः छोटे, ज्ञानी नैनोकणों के रूप में पानी में लौट आए। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि जहां कुछ माइक्रोप्लास्टिक अपने मूल रूप में बने रहते हैं, वहीं अन्य छोटे कणों में विभाजित हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनका पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ सकता है। प्लास्टिक कार्बनिक पदार्थ के रूप में छिपा हुआ है पाचन के दौरान माइक्रोप्लास्टिक में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए, टीम ने एस्क़िडियन द्वारा उत्सर्जित कणों का विश्लेषण करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया। विश्लेषण से एक आश्चर्यजनक परिवर्तन का पता चला- प्लास्टिक के कण अब प्लास्टिक के रूप में पहचाने जाने योग्य नहीं थे। इसके बजाय, वे पाचन तंत्र में प्राप्त मल कोटिंग के कारण कार्बनिक पदार्थ प्रतीत होते थे। -हमारे निष्कर्षों से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक कण एक मल परत के साथ लेपित एस्क़िडियन के पाचन तंत्र से उत्सर्जित होते हैं, और यह संभावना है कि समुद्री पर्यावरण भी इन कणों को इस कार्बनिक पदार्थ के रूप में पहचानता है, - हेरल ने कहा। इस परिवर्तन से इन कणों के मल पर भोजन करने वाले अन्य समुद्री जानवरों द्वारा निवेश जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक खाद्य जाल में शामिल हो जाते हैं। फ़ेकल कोटिंग बैक्टीरिया के उपनिवेशण और भारी



मध्य स्वर्णिम ब्रीफ

भाजपा ने बनाए प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम विधानसभा प्रभारी

बैतूल (मध्य स्वर्णिम)। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के महत्वकांक्षी कार्यक्रम मन की बात के विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत श्री नरेन्द्र मोदी जी महिने के हर अतिम रविवार को रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मान की बात कार्यक्रम के जिला प्रभारी नरेन्द्र गढेकर ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार की अनुमति से बैतूल जिले की पांचो विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। जिला मीडिया सेंटर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैतूल विधानसभा में इंद्रपाल पुण्डे को विधानसभा प्रभारी, घोडाडोगरी विधानसभा में राजेन्द्र मालवीय, आमला विधानसभा में भगवंत सिंह रघुवंशी, भैसदेही विधानसभा से देवीसिंह ठाकुर एवं मुलताई विधानसभा से मनीष माथनकर को मन की बात कार्यक्रम का विधानसभा प्रभारी बनाया गया है।

अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई

रायसेन (मध्य स्वर्णिम)। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था में रिक्त पदों के विरुद्ध सत्र 2024–25 में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय में व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने के लिये अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी हैं। इस संबंध में संचालनालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्राचार्य और शाला प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

लहगडुआ में दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार का सामान चोरी



परासिया (मध्य स्वर्णिम)। तामिया परासिया मार्ग पर लहगडुआ में खाई में गिरी इनोवा कार से अज्ञात चोरों ने सामग्री चोरी कर ली। कार से बैटरी डीजल और साउंड सिस्टम चुरा लिया गया। बुधवार की शाम इनोवा दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इनोवा सवार यात्री महाराष्ट्र के चंद्रपुर के घुगघुस के निवासी हैं। महादेव मेले से दर्शन करके वे वापस लौट रहे थे। लहगडुआ में हनुमान मंदिर के समीप स्टैरिंग और ब्रेक फेल होने से कार सीधे खाई में उतर गई। दुर्घटना में पांच लोगों को चोट आई है। इसमें से एक को गंभीर चोट आई थी। सभी उपचार के लिए परासिया अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को वे आजीम कार को निकालने के लिए पहुंचे। कार निकालने के लिए ट्रैक्टर और मजदूर लेकर वे गए थे। जब कार के पास पहुंचे तो पता चला की कर से सामग्री चोरी चली गई है। कार सवारी यात्री दत्ता ने बताया कि कार का साउंड सिस्टम और बैटरी चुरा ली गई है। डीजल भी चुरा लिया गया है। कार में लगी एलसीडी को खोलने का प्रयास किया गया। लेकिन वह खुल नहीं पाई। जिससे चोरी जाने से बच गई। गौरतलब है परासिया तामिया मार्ग पर जब भी कोई दुर्घटना होती है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन से सामग्री चुरा ली जाती है। पीड़ित की जान का नुकसान तो होता ही है। उनको अपना माल भी गवाना पड़ता है। इस तरह के चोरों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

उमरेठ में शिवाजी जयंती पर निकाली शोभायात्रा



परासिया (मध्य स्वर्णिम)। उमरेठ में बुधवार की रात शिवाजी जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। शिवाजी की प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया गया। बड़ी संख्या में लोग शोभायात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के नेहरू चौक सोनी महल्ला मुख्य मार्ग पुलिस थाना तहसील मोर डुंगरी मार्ग और बायपास मार्ग पर पहुंची मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारे लोगों ने लगाई।

उत्साह के साथ सुबह यात्रा निकाली गई शिवाजी महाराज के शौर्य और बलिदान को याद किया गया।

’जन अभियान परिषद ने नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई

परासिया (मध्य स्वर्णिम)। ग्राम पंचायत मोरडोंगरी कला में गुरुवार को नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। नागरिकों को नशे से मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जिला समन्वयक अख्येश जैन, विकास खंड समन्वयक संजीव भावरकर के दिशा निर्देश पर सेक्टर क्रमांक दो उमरेठ के मेंटर शंकरराम प्रजापति द्वारा ग्राम पंचायत मोरडोंगरी कला में कार्यक्रम किया गया। मोरडोंगरी कला के ग्राम मुजावर पश्चिम रैयत के मवासी ढाना में नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत मोरडोंगरी कला के उपसरपंच पंकज दुबे उपस्थित रहे,। वार्ड पंच ललित लक्ष्मण शीलू, सचिव हीराचंद पवार, सहायक सचिव विनोद वायकर कर्मचारी गण प्रकाश यदुवंशी, सजू सल्लाम, ग्रामीण जन, जितु शीलू, खेमराज शीलू, सुनील शीलू, सहित लाइली बहने उपस्थित रही।

खिरसाडोह में मनाई शिवाजी जयंती

परासिया (मध्य स्वर्णिम)। ग्राम पंचायत खिरसाडोह में शिवाजी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिवाजी का पूजन किया गया। उनके कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर संघ जिला प्रचारक अजय शुक्ला, अनुज पाटकर, उमरेठ भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रसाद कुमार,

मजदूर संघ के जिला मंत्री अर्जुन भारती, पीयूष बत्रा, संतोष डेहेरिया, पार्षद आर्योजन समिति सयोजक ओमकार चंद्रवंशी कार्यकर्ता, विकास शिवहरे, सूरज करष्यप, रूपेश चिल्हसटे, सुमित सल्लाम, राजा वर्मा राजेश बर्देवार, शिशांत यादव सुमित ई, संदीप ई, अमित कुशराम, अंकेश राय, अविनारा ई, आकाश ठाकुर, राहुल लोखंडे, गौतम उपस्थित रहे।

कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आबकारी विभाग की जिला निष्पादन समिति की बैठक सम्पन्न

वर्ष 2025–26 हेतु जारी आबकारी नीति के संशोधनों की दी गई जानकारी



रायसेन (मध्य स्वर्णिम)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आबकारी विभाग की जिला निष्पादन समिति की बैठक कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य एसपी पंकज पाण्डे, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया आदि मौजूद थे। सहायक आबकारी

आयुक्त श्रीमती वंदना पाण्डेय ने बैठक में वर्ष 2025–26 हेतु जारी आबकारी नीति के प्रमुख प्रावधानों एवं वर्तमान नीति में गत वर्ष से हुए संशोधनों के बारे में बिन्दुवार अवगत कराया गया। नवीन नीति में अनुज्ञप्तिधारियों को कांटेक्टर रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन कराने की बाध्यता होने से जिले के वर्तमान 20 सप्ताहों के

अनुज्ञप्तिधारियों को कांटेक्टर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। वर्तमान समस्त लायसेंसियों द्वारा कांटेक्टर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन करा लिया गया है, यह विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अवैध मदिरा निरंतर करें कार्यवाही ~कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में

आबकारी विभाग की जिला निष्पादन समिति की अयोजित बैठक में कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा ने समस्त वृत्त उपनिरीक्षकों को अवैध मदिरा विक्रय पर निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वही अतिरिक्त सदस्य जिल सूचना अधिकारी दीपेन्द्र 2024–25 में प्राप्त वार्षिक मूल्य रूपए 3136615482 एवं 20 प्रतिशत वृद्धि पश्चात वर्ष 2025–26 का आरक्षित मूल्य 3763938588 है। वर्ष 2025–26 ठेका निष्पादन कार्यवाही प्रथमता नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन किए जाने के लिए जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की बैठक आहूत की गई जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों से जारी नीति निर्देश के बारे में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य इच्छुक आवेदकों को भी नवीन आबकारी नीति के बारे में अवगत कराया गया है।

डाइट ने जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीते 28 पदक कबड्डी, हार्ड और लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान हासिल किया

रायसेन (मध्य स्वर्णिम)।



डाइट के विद्यार्थियों ने विदिशा में आयोजित जोन स्तरीय खेलकूद व साहित्यिक प्रतियोगिताओं में उच्छ्रे प्रदर्शन किया। 17 से 20 फरवरी तक चली इन प्रतियोगिताओं में रायसेन के छात्रों ने कुल 28 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। प्रतियोगिताओं में रायसेन के खिलाड़ियों ने कई विधाओं में सफलता हासिल की। कबड्डी और हार्ड और लॉन्ग जंप में टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में रजनी इमने लंबी कूद मेंए बलौराम ने 800 मीटर दौड़ मेंए तपस्या लोधी ने शतरंज में शीर्ष स्थान हासिल किया। वाद,विवाद में रागिनी रघुवंशी और कविता लेखन में सेजल धाकड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन~ डाइट की

प्राचार्य कमला कुचूर ने विजेताओं को बधाई दी। सभी विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। क्रीड़ा प्रभारी किरण प्रसाद सिंह ने कहा कि भविष्य में डाइट रायसेन में और अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एममोल राठौरिया, संजीव जैन, कमलेश बहादुर, मनोहर सिंह राजपूत, समेत समस्त डाइट स्टाफ उपस्थित रहा।

माथनी खदान में नहीं होंगे ट्रांसफर, सामान भी नहीं निकलेगा

परासिया (मध्य स्वर्णिम)। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की गुरुवार को छह बजे पंच परिया प्रबंधन के साथ वार्ता हुई। वार्ता में प्रबंधन के साथ सकारात्मक नतीजे निकले। प्रबंधन खदान से मजदूरों के ट्रांसफर नहीं करने और सामान नहीं निकालने के के लिए सहमत हुआ। इसके बाद बीएमएस ने क्रमिक अनशन खत्म कर दिया। माथनी कोयला खदान को गैस के कारण प्रबंधन ने बंद कर दिया था। इसको लेकर बीएमएस ने स्टार्क नोटिस देकर क्रमिक अनशन शुरू किया था। वेकालि पंच परिया प्रबंधन के साथ बीएमएस के स्थाई खान सुरक्षा समिति सदस्य भारत सरकार, नारायण राव सराठकर, पंच कन्हान अध्यक्ष रामसिंह बघेल, महामंत्री तेज प्रताप शाही, कुंवर सिंह, संजय बावरिया भुवनेश्वर यदुवंशी, आशीष यादव, नरेश कुमार, अशोक डोंगरे, अख्खलाल गुप्ता, दिवला निषाद आदि की उपस्थिति में वार्ता हुई। वार्ता के बाद अनशन स्थल पर जाकर अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को दूध पीलाकर अनशन खत्म कराया गया।

चौरागढ के महादेव बाबा के दर्शन के लिए पैदल जाएंगे सांसद बंटी साहू
परासिया (मध्य स्वर्णिम)। सतपुड़ा की चोटी पर चौरागढ में महादेव बाबा के दर्शन के लिए पुरातन काल से मेला आयोजित होता है। शुक्रवार को इस मेले में अनूठा इतिहास जुड़ने वाला है। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू सांगाखेड के भूराभगत से पैदल चढाई कर महादेव बाबा के दर्शन के लिए निकलेगे। सुबह साढे छह बजे वे छिंदवाडा से सफर शुरू करेंगे। सांगाखेड भूराभगत में बाबा भूराभगत के दर्शन कर वे नौ बजे महादेव की यात्रा आरंभ करेंगे। इस मार्ग में हेलीकाप्टर से सांसद जरूर गए हैं। पहली बार सांसद बंटी साहू पैदल यात्रा कर पहाड पर पहुंचेगे।

परीक्षा के पहले बच्चों को आवासीय क्लासेस से किया जा रहा तैयार

निर्तिन दत्ता तामिया (छिंदवाड़ा)

दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले स्कूल में नवाचार कर बच्चों को तनावमुक्त कर परीक्षा की तैयारी कराने को लेकर सतपुड़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पांडुपिपरिया चर्चाओं में है यहां 15 दिन के लिए 30 छात्रों को आवासीय व्यवस्था के साथ अनुशासित विविध गतिविधियों के साथ तैयार किया जा रहा है। सतपुड़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पांडुपिपरिया के संचालक अमन साहू ने बताया कि कक्षा 12 और 10 की बोर्ड परीक्षा 25–27 फरवरी से शुरू हो रही है। 18 फरवरी से कक्षा 10 के 14 तथा 12 के 16 कुल 30 विधार्थियों के लिए आवासीय पढ़ाई कराने की व्यवस्था की गई है। यहां बच्चे अलसुबह 4 बजे योग व्यायाम के साथ अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद स्कूल की पढ़ाई के



बाद शाम 5 बजे से 9 बजे तक फिर कक्षाएं लगती हैं। यहां पर हर विषय के शिक्षक विषयवार तैयारी करा रहे हैं। बीते 8 से 22 फरवरी तक के लिए रैसिडेंशियल स्पेशल क्लास प्रोग्राम में बच्चे उत्साह से जुटे हैं। पढ़ाई के साथ समय समय पर अन्य गतिविधियां होती हैं। प्रिंसीपल नम्रता डेनियल, अर्पित दत्ता, अलीसामा सोना अनिल सर अन्य शिक्षक विषयवार पढ़ा रहे हैं। डायरेक्टर अमन साहू ने बताया की अलसुबह मेडिटेशन योगा स्कूल की पढ़ाई और नाश्ते के बाद स्कूल के समय बच्चे रूटीन क्लासेस में रहते हैं। विशेष कक्षाओं के लिए आवासीय व्यवस्था ऊपरी हाल में की गयी है।

दिनों आगामी 15 दिनों के लिए आवासीय विधालय में बदल गया है। पालकों द्वारा परीक्षा के पहले बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही की शिकायत आम है ऐसे में स्कूल के डायरेक्टर अमन साहू ने शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयोग किया है। यहां स्कूल में 30 छात्रों के लिए स्कूल के साढ़े नौ से चार बजे के समय के बाद डेढ़ घंटे के खेल कालखंड के बाद डेढ़ घंटे के तीन विषय की अलग अलग क्लास लगती है जिसमे प्रिंसीपल नम्रता डेनियल अंग्रेजी वास्ड प्रिंसीपल अनित दत्ता, अलीसामा सोना अनिल सर अन्य शिक्षक विषयवार पढ़ा रहे हैं। डायरेक्टर अमन साहू ने बताया की अलसुबह मेडिटेशन योगा स्कूल की पढ़ाई और नाश्ते के बाद स्कूल के समय बच्चे रूटीन क्लासेस में रहते हैं। विशेष कक्षाओं के लिए आवासीय व्यवस्था ऊपरी हाल में की गयी है।



दिन चार मैच खेले गए। पहला मैच शैलेश 11 केटीआर के बीच खेला गया जिस में केटीआर 4 विकेट से मैच जीता लिया। जिसमें मेन ऑफ था मैच अंशुल को दिया गया। वहीं दूसरा मैच आशीष 11 और पठान 11 के बीच खेला गया जिस में आशीष 11 ने 34 रनों से मैच जीता, और आशीष 11 के खिलाड़ी अनित को मेन ऑफ द मैच दिया गया। तीसरा मैच युवराज 11 व रायसेन

11 के बीच खेला गया जिस में रायसेन 11 ने आसानी से मैच जीत लिया शानदार पारी की वजह से मोनू यादव को मेन ऑफ मैच दिया गया। चौथा मैच जीतू 11 व शैलेश 11 के बीच खेला गया जिस में जीतू 11 ने यह मैच जीता। मैच में समिति के सदस्य दीपक थोरात, रवि गुरनानी, मुशीर, मोनू, विजय नामदेव, हिममत राजपूत, सुमित आदि मौजूद थे।

अंबाडा में तेज रफ्तार कार दो लोगों को रौंदकर टैंकर में घुसी, दोनों मौत

इवनिंग वाक कर रहे दो बुजुर्ग और कार सवार वृद्ध की मौत

परासिया (मध्य स्वर्णिम)।

परासिया जामई मार्ग पर गुरुवार की शाम एक तेज रफ्तार वेगनार कार ने सड़क पर इवनिंग वाक कर रहे दो बुजुर्गों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्गों को रौंदने के बाद कार समीप खड़े टैंकर में घुस गई। कार में सवार बुजुर्ग को जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकालना पड़ा। बाद में उनकी भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद इवनिंग वाक पर निकले बुजुर्गों को परासिया अस्पताल लाया गया। यहां दोनों बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया गया। वही कार सवार घायल बुजुर्ग को कुछ देर बाद कार से निकालकर लाया गया। उनका उपचार किया गया। इसके बाद उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में मृत जवाहित गुप्ता और महादेव पवार दोनों पंडीसी है। वे रोजाना शाम को इवनिंग वाक के लिए जाते थे। आज भी दोनों साथ निकले और साथ ही दोनों की जान चली गई। आज उनका इवनिंग वाक अंतिम वाक बन गया।

प्रमुख सचिव ने वीसी के माध्यम से की गेहूं उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने जिले में गेहूं उपार्जन हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश



रायसेन (मध्य स्वर्णिम)।

रबी विपणन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में भोपाल तथा नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 01 मार्च 2025 से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वीसी कक्ष से कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा तथा संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक के उपरांत कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा ने जिले में प्रमुख सचिव के निर्देशों के अनुरूप जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में समर्थन मूल्य

पर गेहूं उपार्जन कार्य 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। उपार्जन केन्द्रों पर एफएन्यू गुणवत्ता का ही गेहूं खरीदा जाए। कलेक्टर विश्वकर्मा ने उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं की सफाई हेतु पंखा, छाना आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, किसान भाईयों के लिए छायादार बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। किसान पंजीयन की जानकारी लेने पर अवगत कराया गया कि जिले में 20 जनवरी से 117 पंजीयन केन्द्रों में समितियों द्वारा निशुल्क किसान पंजीयन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले में एमपी ऑनलाइन के 36, कॉमन सर्विस सेंटर के 141, साईबर कैफे आदि के माध्यम से 50 रु शुल्क के साथ किसान पंजीयन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्वयं के मोबाईल से भी पंजीयन कर सकते हैं।

40 नट परिवारों पर इस्लाम धर्म अपनाने का आरोप, डॉ अंबेडकर जन कल्याण समिति ने दर्ज कराई शिकायत

मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 10 दिन में एसपी से मांगा जवाब

रायसेन (मध्य स्वर्णिम)।

जिले के गैरतगंज तहसील के पापड़ा गांव में अनुसूचित जाति के 40 नट समुदाय के परिवारों का इस्लाम धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। डॉ अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल के अध्यक्ष सुनील अहिरवार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि गांव में बच्चों और ग्रामीणों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। इन परिवारों ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेना जारी रखा। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27 अगस्त 1950 के अनुसार हिंदू धर्म से बौद्ध या सिख धर्म अपनाने वालों को ही अनुसूचित जाति



के आरक्षण का लाभ मिलता है। मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये परिवार मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यह प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले को संज्ञान में

लिया। कलेक्टर और एसपी को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के तहत जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दस दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग ने 10 दिन में मांगी विस्तृत रिपोर्ट : मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रायसेन कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पाण्डेय से जवाब मांगा है। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामले को संज्ञान में लिया है। अधिकारियों को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के तहत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

उमरेठ के खजरी अंतु में बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय भूमि का अवलोकन किया

परासिया (मध्य स्वर्णिम)। उमरेठ के खजरी अंतु में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है। इसको राजस्व कर्मचारियों के साथ भाजपा के प्रतिनिधियों ने शासकीय भूमि का अवलोकन किया। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से ग्राम पंचायत खजरी अंतु में 65 लाख की लागत से उपस्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इस भवन के निर्माण के लिये मंडल अध्यक्ष राकेश बेलवंशी ने आज शासकीय भूमि का अवलोकन किया। राजस्व एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच नीरज कोलारे, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश भुवें, मंडल उपाध्यक्ष गण अंकुश जायसवाल, बाबी रघुवंशी, हेमंत सिंह चौहान, नवीन जायसवाल, पटवारी किरण पवार पंचायत सचिव सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे।



चरई कला में पाइपलाइन फोड़ने को लेकर विवाद परासिया (मध्य स्वर्णिम)। बड़कुही पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव चरई कला में खेत में पाइपलाइन फोड़ने को लेकर गुरुवार को विवाद हुआ। विवाद में दंपति को पीटा गया। मामले की शिकायत बड़कुही पुलिस चौकी में की गई। ग पुलिस ने दंपति का मुलाहजा कराया। घटना को लेकर सतीश यदुवंशी ने बताया कि वह अपनी पत्नी करुणा के साथ खेत में पानी भाग रहा था। प्रडोंसी संजय यदुवंशी ने उसकी पाइपलाइन को फोड़ दिया। उसने पाइपलाइन फोड़ने का कारण पूछा तो आरोपी ने पहले उसे मारा। उसके बाद उसकी पत्नी को भी पीटाई कर दी। उसकी पत्नी के हाथ और पैर में चोट आई है। सतीश को भी हाथ पैर और पीठ में चोट आई है पुलिस मामले की जांच कर रही है।





भोपाल अब सिर्फ मध्यप्रदेश की राजधानी नहीं, बल्कि भारत के नए औद्योगिक भविष्य का प्रतीक बनने की ओर अग्रसर है।

जीआईएस-2025 इसी परिवर्तन की मजबूत नींव रखने जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। देश-विदेश के 20 हजार से अधिक निवेशक, उद्योगपति एवं अन्य महानुभाव होंगे शामिल। साथ ही 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समिट में शहरी विकास से लेकर आईटी तक, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर टूरिज्म तक – हर सेक्टर पर फोकस्ड सेशन होंगे। मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु एमएसएमई समिट एवं प्रवासी मध्यप्रदेश समिट आयोजित की जाएगी। ग्लोबल साउथ सेशन के माध्यम से विकासशील देशों के साथ नई साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जीआईएस इनोवेटर्स, स्टार्ट-अप्स फ़ाउंडर्स और उद्योग लगाने वाले युवाओं के लिये बिज़नेस ग्रो करने का सुनहरा अवसर है। मध्यप्रदेश तेजी से उभरते हुए औद्योगिक और निवेश हब के रूप में स्थापित हो रहा है। जीआईएस-2025 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां वैश्विक और राष्ट्रीय निवेशक राज्य की असीम संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में हुआ कर्टन रेजर कार्यक्रम मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा। आइए, हम सभी मिलकर मध्यप्रदेश को निवेश और विकास का आदर्श केंद्र बनाएं।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश शासन

उद्योग फ्रेंडली नीतियाँ और नवाचार से मिलेगा निवेश को विस्तार

मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश और रणनीतिक नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट न सिर्फ अपनी भव्यता बल्कि गहरे रणनीतिक बदलावों और नए औद्योगिक विज़न से भी चर्चा में है। भोपाल, जो अब तक प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से पहचाना जाता था, अब निवेश और व्यापार का नया ग्लोबल पॉइंट ऑफ़ इंटररेस्ट बनने जा रहा है। झीलों की नगरी भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। भोपाल का आकर्षण और राज्य सरकार की सहज एवं पारदर्शी उद्योग फ्रेंडली नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।

नवाचारों का केन्द्र बनेगा जीआईएस

इस वर्ष के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को 'पॉलिसी-ड्रिवन इन्वेस्टमेंट समिट' का नया मॉडल दिया गया है। पहली बार, सरकार 20 से अधिक नीतियों को एकसाथ प्रस्तुत कर रही है, जिससे निवेशकों को हर सेक्टर के लिए स्पष्ट रणनीति और अवसर मिलेंगे। अब इन्वेस्टर्स को केवल संभावनाएँ नहीं, बल्कि सरकार की ठोस योजनाओं और तत्काल प्रभावी पॉलिसी सपोर्ट का भरोसा

मिलेगा।

इस बार का GIS पारंपरिक कॉन्फेंस से आगे बढ़कर 'फोकस्ड इन्वेस्टमेंट डिस्कशन' का मंच बनने जा रहा है। यानी, आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ईवी, अक्षय ऊर्जा जैसे हर सेक्टर के लिए अलग सत्र होंगे, जहां इंडस्ट्री लीडर्स और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद और सेक्टर-केंद्रित समझौते होंगे। समिट में पहली बार 'इंडस्ट्रियल एक्सपो' और 'मेक इन एमपी' का संयोजन किया गया है, जहां प्रदेश की औद्योगिक ताकत, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी स्थिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

जीरो अपशिष्ट समिट

जीआईएस-2025 को 'जीरो अपशिष्ट' समिट बनाने की



रणनीति तैयार हो चुकी है। समिट स्थल पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा, आयोजन स्थल 100% अक्षय ऊर्जा से संचालित होगा और पूरे समिट में पेंपरलेस ऑपरेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड इंटरैक्शन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश होगा।

औद्योगिक राजधानी के रूप में नई पहचान

भोपाल को पहली बार औद्योगिक राजधानी के रूप में नई पहचान मिलने जा रही है। यह आयोजन प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल जर्नी की आधारशिला साबित होगा। समिट न केवल बड़े निवेशकों के लिए बल्कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ा अवसर लेकर आ रही है। प्रदेश के स्थानीय उद्यमों को वैश्विक निवेशकों

और तकनीकी साझेदारों के साथ जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे इनका विस्तार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक होगा। राजधानी के चारों ओर फैले औद्योगिक क्षेत्रों—मंडीदीप, गोविंदपुरा, बागरोदा, पिलुखेड़ी और अन्य औद्योगिक हब को इस समिट से नए निवेश, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टाई-अप्स का फायदा मिलेगा। जीआईएस-2025 केवल निवेश ही नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर देने वाला मंच भी साबित होगा। इस समिट में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर पैदा करने वाले एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।

औद्योगिक क्रांति का केन्द्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अब केवल 'संभावनाओं का प्रदेश' नहीं, बल्कि 'औद्योगिक क्रांति का अगला केंद्र' बन चुका है। GIS 2025 के मंच से प्रदेश की आर्थिक शक्ति, नीति-संवर्धित औद्योगिक मॉडल और वैश्विक निवेश के प्रति प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी।

टेलेंट और इनोवेशन को बढ़ावा

प्रदेश सरकार के फोकस में उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ टेलेंट और इनोवेशन को बढ़ाते हुए आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर हब और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण निवेश है। अग्रणी तकनीकी हब बनने की दृष्टि के साथ मध्यप्रदेश डिजिटल भविष्य को शक्ति प्रदान करने के रास्ते पर अग्रसर है। आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है, जो कैपेक्स, भूमि, ब्याज छूट, मार्केटिंग और पेटेंट सहायता आदि प्रदान करती है। दूसरी ओर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025 वैश्विक तकनीकी केंद्रों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कैपेक्स, पेरोल और अपरिक्लिंग के लिए सब्सिडी, आरएंडडी को सपोर्ट करती है। इसी तरह एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी-2025 एवीजीसी सेक्टर को सपोर्ट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, उत्पादन संबंधी वित्तीय सहायता, उद्योग सहयोग और एवीजीसी-एक्सआर लैब की स्थापना आदि के लिए सहयोगी है। इसके अलावा ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 ड्रोन निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कैपेक्स सहायता, ड्रोन पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के साथ ड्रोन अपनाने को बढ़ावा देती है।

आईटी और प्रौद्योगिकी में मध्यप्रदेश करेगा डिजिटल भविष्य का निर्माण

जीआईएस से खुलेंगे प्रगति के नए द्वार- परिवर्तनकारी निवेशों की लहर

आईटी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से नई ऊर्जा मिलेगी। इस सेक्टर के लिए समिट में अलग से सत्र आयोजित होगा। मध्यप्रदेश में 15 से अधिक आईटी पार्क और 5 आईटी एसईजेड हैं, जिनमें इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क और इंफोसिस जैसे प्रमुख सेंटर शामिल हैं। ये पार्क विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हैं, जो टीसीएस, इंफोसिस और एक्सचेंजर जैसी प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करते हैं। नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 जैसी आगामी परियोजनाएं, इस इको सिस्टम को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन के दौर से गुजर रहे देश के तकनीकी इको सिस्टम के विकास के अगले केन्द्र टीयर-2 शहर हैं, जो टेक इनोवेशन और निवेश के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसकी वजह है यहां कम परिचालन लागत, उच्च जीवन स्तर और कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता। टीयर-2 शहर अब तकनीकी कंपनियों की पसंद बनते जा रहे हैं। खास बात है कि मध्यप्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलेंट और लागत-दक्षता प्रदान करने वाला अग्रणी राज्य है। मध्यप्रदेश का व्यापक आईटी, आईटीईएस और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। विश्व स्तरीय आईटी पार्क, नॉलेज और सॉफ्टवेयर हब के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने से निश्चित रूप से मध्यप्रदेश तकनीकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करेगा।

परिवर्तनकारी निवेशों की लहर



मध्यप्रदेश ने परिवर्तनकारी निवेशों की एक लहर देखी है, जो भारत के अगले बड़े तकनीकी केन्द्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। इंदौर में एलटीआई माइंडट्री का 870 करोड़ रुपये का तकनीकी परिसर 10 हजार से ज्यादा नौकरियां प्रदान करेगा, जो आईटी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं में मध्यप्रदेश की भूमिका को मजबूत करेगा। रैकबैक का डेटा सेंटर विस्तार में 644 करोड़ रुपये का निवेश मध्यप्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे और वलाउड सेवाओं को मजबूत कर रहा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और कॉमिनजेंट क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 80 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपनी उपस्थिति का और विस्तार कर रहे हैं। ये परियोजनाएं साल 2024 में हासिल किए गए 2,500 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी निवेश के साथ मध्यप्रदेश को पारंपरिक आईटी केंद्रों के समक्ष एक बेहतर और सक्षम विकल्प बनाती हैं।

देश की डिजिटल क्रांति के साथ तालमेल

मध्यप्रदेश न केवल देश की डिजिटल क्रांति के साथ तालमेल बना रहा है, बल्कि यह इसका नेतृत्व भी कर रहा है। एआई, साइबर सुरक्षा, एवीजीसी-एक्सआर और ड्रोन में राज्य का विज़न इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की अगली लहर के लिए आधार तैयार कर रहा है। एआई और साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) की स्थापना, आगामी एवीजीसी, मीडिया पार्क और इनक्यूबेशन हब के साथ, अत्याधुनिक अनुसंधान और उद्योग सहयोग के लिए मध्यप्रदेश प्रतिबद्ध है। प्रगतिशील नीति ढांचे, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और प्रचुर प्रतिभा पूल के साथ मध्यप्रदेश भारत का अगला प्रमुख टेक पॉवरहाउस बनने के रास्ते पर अग्रसर है।

भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा

प्रदेश में निर्बाध परिवहन नेटवर्क है। इससे निवेशकों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 46 राष्ट्रीय राजमार्ग, 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन और 6 क्रियाशील हवाई अड्डे हैं। उन्नत व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए इंदौर और जबलपुर में आगामी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी प्रस्तावित है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 - शहरी विकास पर भी होगा विशेष फोकस

झीलों की नगरी भोपाल में निवेश का महाकुंभ झीलों की नगरी भोपाल में निवेश के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शहरी विकास के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, मजबूत बुनियादी ढांचा, निर्बाध विकास के चलते मध्यप्रदेश भारत के शहरी परिवर्तन में अग्रणी राज्य है, जो रणनीतिक निवेश, सतत विकास और अत्याधुनिक डिजिटल गवर्नेंस का संयोजन कर रहा है। प्रदेश में 72 हजार करोड़ रुपये की चल रही शहरी परियोजनाओं और 88 हजार करोड़ रुपये की आगे आने वाली परियोजनाओं के साथ राज्य तेजी से अपने बुनियादी ढांचे, आवास और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का विस्तार कर रहा है। सात स्मार्ट सिटी, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और प्रगतिशील शहरी नीतियों के साथ मध्यप्रदेश निवेशकों और डेवलपर्स के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की स्थिति में है। प्रदेश में शहरी विकास की योजनाओं में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन योजनाओं के जरिये रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी



शहरी विकास में मध्यप्रदेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, इसकी बड़ी वजह है 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 7 स्मार्ट सिटी और 72 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं, साथ ही पाइपलाइन में 88 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं। प्रदेश में 8.32 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है, वहीं 50 हजार करोड़ रुपये से 10 लाख नए आवासों की योजना प्रस्तावित है। शहरी विकास के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक 100 प्रतिशत पूरा किया जाएगा। प्रदेश में 6000 किलोमीटर शहरी सड़कें गतिशीलता और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं। प्रदेश में वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत सीवर कवरेज कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मध्यप्रदेश स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 2 राज्यों में रहा है। इंदौर ने लगातार सातवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और सर्वेक्षण में पांचवें स्थान पर रहा है।

ड्रोन नीति की कृषि के क्षेत्र में होगी महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों की अहम भूमिका है। कृषि के क्षेत्र में किए गए निवेश से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी राज्य सरकार ने ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। ड्रोन से फसल की सेहत की निगरानी, रोगों का पता लगाने और फसल की पैदावार का मूल्यांकन करने में सहायता मिल रही है। ड्रोन उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव सटीकता से कर सकते हैं, जिससे अपशिष्ट और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा। वे

उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें अधिक या कम पानी की आवश्यकता है। सिंचाई के तरीकों का बेहतर उपयोग करने में ड्रोन मदद करता है। नक्शा कार्यक्रम से शहरी क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर भूमि अभिलेखों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि स्वामित्व की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये बेहतर एवं अनुकूल वातावरण है। यहां पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं भी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक उद्योग मित्र नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इन नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र की हर समस्या का समाधान होगा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में नई सुविधाएं, सब्सिडी और अनेक तरह की छूटें भी मिलेंगी। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनेक नई नीतियों को मंजूरी दी गई है।



मध्य स्वर्णिम ब्रीफ

ऑटोमोबाइल में क्रांति का नया केंद्र बन कर उभर रहा है मध्यप्रदेश

भोपाल। भारत में औद्योगिक भविष्य की रूपरेखा अब मध्यप्रदेश से तय हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य न केवल आदर्श निवेश स्थल बन कर उभर रहा है बल्कि ऑटोमोबाइल और ईवी इंडस्ट्री के एडवांस इरा की नई परिभाषा लिख रहा है। डेट्रॉयट जिस तरह 20वीं सदी में ऑटोमोबाइल क्रांति का केंद्र बना था, उसी तरह 21वीं सदी में मध्यप्रदेश ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत का प्यूचर हब बनकर उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (नवंबर-2025) इस बदलाव का एक ऐतिहासिक मंच बनेगा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल और ईवी कंपनियां मध्यप्रदेश के औद्योगिक भविष्य को आकार देने के लिए आगे आएंगी। यह सिर्फ निवेश आकर्षित करने का अवसर नहीं, बल्कि भारत में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और ई-मोबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मंच है। भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति की चर्चा अब पारंपरिक हब्स तक सीमित नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की उद्योग अनुकूल नीतियों और विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक पहुंच चुकी है।

अनमोल आरसीएच पोर्टल के नवीन संस्करण 2.0 का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विकसित अनमोल आरसीएच पोर्टल के नवीन संस्करण 2.0 को लागू करने हेतु जिलों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 138 प्रशिक्षकों को नवीन अनमोल मोबाइल एप्लिकेशन एवं वेबपोर्टल के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि अनमोल ऐप के विधिवत उपयोग से बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। जिससे गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन होगा। अनमोल आरसीएच पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग और प्रबंधन को सरल बनाता है। नवीन संस्करण में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, हाई-रिस्क गर्भावस्था की पहचान, प्रसव संबंधी रिकॉर्ड, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की एट्री की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया गया है। इससे जिले और राज्य स्तर पर इन सेवाओं की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्मार्ट मीटर स्थापना

भोपाल। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पंद्रहवें जिला मुख्यालय बुरहानपुर में भी अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है। यहां एक हजार स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं। इससे पहले इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, आलीराजपुर, झाबुआ, धार में स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। कंपनी के झाबुआ और खरगोन जिला मुख्यालय शत प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाले शहर घोषित कर दिए गए हैं। कंपनी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर इंदौर शहर में 4.75 लाख स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं कंपनी क्षेत्र के 45 नगरीय निकायों में अब तक 10 लाख 50 हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं। प्रतिदिन स्मार्ट मीटरीकरण का कार्य जारी है।

जीआईएस-2025, भोपाल में होगा वैश्विक निवेशकों का महासंगम

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 को लेकर तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं और विशिष्ट मेहमानों की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इसमें 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महावाणिज्यदूतों की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अनुदी पहल देश के महानगरों में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और युके, जर्मनी और जापान में निवेशकों को आकर्षित करने रोड-शो के आयोजन ने न सिर्फ क्षेत्रीय उद्योगों को एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म दिया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राजनयिक कोर की भागीदारी का नेतृत्व जर्मनी, जापान, स्विटजरलैंड और मलेशिया के महावाणिज्यदूतों सहित मिशनों के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड और कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

पहली बार भोपाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चौधरी

बोलें- मिशन एमपी पर करूंगा काम, राजनीतिक समझ शून्य

भोपाल। हालही में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हरीश चौधरी गुरुवार को पहली बार भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने चौधरी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से पीसीसी तक जगह-जगह नेताओं ने अलग-अलग स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं शून्य समझ के साथ आया हूं। यहां पर सहयोगी की भूमिका में रहकर मिशन मध्य प्रदेश पर काम करूंगा। मेरी राजनीतिक समझ शून्य है। हरीश चौधरी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले। चौधरी ने पीसीसी में कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, विभा पटेल सहित कई विधायक,

मुख्य सचिव जैन ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बुलाई बैठक, की समीक्षा

परीक्षाओं में अवरोध न उत्पन्न होने देने के दिये निर्देश



भोपाल। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर भोपाल एवं पुलिस-कमिश्नर को निर्देशित किया कि जीआईएस के दौरान होने वाली परीक्षाओं में कोई अवरोध नहीं हो।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्मार्ट मीटर स्थापना

भोपाल। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पंद्रहवें जिला मुख्यालय बुरहानपुर में भी अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है। यहां एक हजार स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं। इससे पहले इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, आलीराजपुर, झाबुआ, धार में स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य प्रारंभ

कर दिया गया था। कंपनी के झाबुआ और खरगोन जिला मुख्यालय शत प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाले शहर घोषित कर दिए गए हैं। कंपनी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर इंदौर शहर में 4.75 लाख स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं कंपनी क्षेत्र के 45 नगरीय निकायों में अब तक 10 लाख 50 हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं। प्रतिदिन स्मार्ट मीटरीकरण का कार्य जारी है।

ग्वालियर को हर दृष्टिकोण से आदर्श शहर बनायेंगे: तोमर



भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर शहर के वार्ड-33 के अंतर्गत लक्ष्मण तलैया जीर्णोद्धार कार्य व सीसी रोड निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। यह कार्य एक करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से होने जा रहे हैं। मंत्री तोमर ने कहा कि उपनगर

उपलब्ध हों। मंत्री तोमर ने कहा कि लक्ष्मण तलैया के जीर्णोद्धार के साथ-साथ यहाँ पर एलईडी लाइट, वाटर फाउंटेन, बेंच, शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड आदि कार्य कराये जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि लक्ष्मण तलैया एक टूरिस्ट प्लेस बने और पर्यटक लक्ष्मण तलैया को देखने आएँ। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीर्णोद्धार के साथ ही इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाए। मंत्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर का वैभव पुराने स्वरूप में दिखे। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा एतिहासिक स्थलों को संवारने का कार्य किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्री सारंग को स्कॉच अवॉर्ड सौंपा

मार्कफेड को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड

भोपाल। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को गुरुवार को मंत्रालय में प्रबंध संचालक विपणन संघ आलोक कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्राप्त 'स्कॉच' अवॉर्ड सौंपा। नई दिल्ली के इण्डिया हेब्रिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रबंध संचालक विपणन संघ सिंह की ओर से आईएफएसएस प्रोजेक्ट हेड श्रीमती मंदिरा लोध एवं प्रोजेक्ट मैनेजर नितेन्द्र सिंह द्वारा अवॉर्ड ग्रहण



किया गया। मंत्री सारंग द्वारा खाद वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर उर्वरक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के निर्देश उर्वरक वितरण की नोडल एजेंसी

कार्ड, बैठक व्यवस्था, होटल, स्वास्थ्य, मेहमानों के भोजन, आकस्मिक प्लान, प्रधानमंत्री की आगमन-प्रस्थान व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों को समझकर निर्वहन करें। टीम वर्क के साथ कार्य करें जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके।

बैठक में स्वास्थ्य, नवकरणीय ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, उद्यानिकी, खनिज साधन, पर्यटन एवं एमएसएमई विभागों ने प्रेजेंटेशन देकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, मनु श्रीवास्तव, अनुपम राजन, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, उमाकांत उमराव, राघवेंद्र सिंह सचिव, सुदाम पी. खाड़े, एम. रघुराज कलेक्टर भोपाल एवं पुलिस कमिश्नर उपस्थित थे।

निरोगी काया अभियान 2025 का हुआ शुभारंभ

31 मार्च तक 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी रोगों की निःशुल्क की जाएगी जाँच

भोपाल। मध्यप्रदेश में 'निरोगी काया अभियान' 20 फरवरी से 31 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत प्रदेशभर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी रोगों की निःशुल्क जाँच की जायेगी।

अभियान का मुख्य उद्देश्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी

24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक 139 नृत्य कलाकारों ने वृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन से बनाया गिनीज रिकॉर्ड



भोपाल। ईश्वर की साधना को समर्पित वृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन गिनीज विश्व रिकॉर्ड से नृत्य साधकों का मान बढ़ेगा। यह देश की संस्कृति और नृत्यसाधकों के लिए गौरव का क्षण है। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और विश्व पटल पर अंकित करने का यह सर्वोत्तम साधन है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिनीज विश्व रिकॉर्ड से पूरा विश्व भारत की विविध और समृद्ध संस्कृति से प्रकाशमान होगा। 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक 139 नृत्य कलाकारों की अविरल और साधना से बना विश्व रिकॉर्ड न सिर्फ कला साधकों का हौसला

बढ़ाएगा बल्कि शासन के संस्कृति और विरासत को सहेजने के प्रयासों को भी गति देगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पावन और पवित्र है। बुंदेलखंड की धरती पर पत्थर भी चमकता है तो हीरा कहलाता है। मनुष्य चमकता है तो बुंदेला कहलाता है। वैसे ही बुंदेलखंड में नृत्य होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह कहलाता है। डॉ. यादव ने कहा कि शास्त्रीय नृत्यों का सृजन भगवान की साधना के लिए किया गया है। जैसे कथकली में भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला, जीवन और गतिविधियों को दिखाया जाता है। वहीं, भगवान नटराज ने तांडव नृत्य और आनंद नृत्य का सृजन किया है।

बीमारियाँ प्रारंभिक अवस्था में बिना लक्षणों के होती हैं, लेकिन आगे चलकर हृदय रोग, लकवा, किडनी व लीवर की बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य जांच, रोग की शीघ्र पहचान और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अभियान का विशेष लाभ जनजातीय एवं वनवासी समुदायों को मिलेगा। इन्हें रोगों की रोकथाम, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशे से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें।

भेड़ चराने वाले निकले स्मगलर, दो लाख की अफीम के साथ दो राजस्थानी तस्कर गिरफ्तार



शिवपुरी। शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो भेड़ चराने के बहाने अफीम तस्करी में लिप्त थे। पुलिस ने उनके पास से 2 लाख रुपये मूल्य की 1 किलो अफीम बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कालुराम पुत्र कानाराम रईका (उम्र 45 वर्ष) और कोजाराम पुत्र स्व. गूदडराम उर्फ गिरधारी रईका (उम्र 62 वर्ष), निवासी राइकों का बास वस्सी, पाली, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मेड़ पालक बनकर करते थे तस्करी

शिवपुरी के देहात थाना प्रभारी रंजेश यादव ने बताया कि आरोपी राजस्थान से आकर शिवपुरी जिले के ग्रामीण इलाकों में अफीम तस्करी करते थे। वे भेड़ पालक बनकर घूमते थे ताकि उन पर शक न हो। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिंपरसमां अनाज मंडी के पास

कच्चे रास्ते पर घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा।

राजस्थान से लगी सीमा होने के कारण तस्करी में आसानी

शिवपुरी जिले की सीमा राजस्थान से लगती है, जिससे यहां नशा तस्करों के लिए तस्करी करना आसान हो जाता है। राजस्थान से आने वाले तस्कर यहां अफीम, स्पैक और अन्य नशे की सामग्री बेचते हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार, ये तस्कर ग्रामीण इलाकों में नशे की सामग्री खपाते थे।

पूछताछ में जुटी पुलिस

दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अफीम राजस्थान के किस इलाके से लाते थे और कहां-कहां सलाई करते थे। पुलिस उनके अन्य साथियों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि इस गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।